

*इंडिया जस्टिस रिपोर्ट रैंकिंग 2019 का हिस्सा नहीं



पुलिस

डेटा को कैसे पढ़ें : चूंकि प्रत्येक संकेतक की एक अलग इकाई होती है, इसलिए तुलना करने के लिए, हमने 1 से 10 के बैंड में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन की गणना करने हेतु मूल्यों के लिए एक नया आधार स्तर तैयार किया है। लाइन ग्राफ यह दर्शाता है कि केंद्र शासित प्रदेश, प्रत्येक संकेतक पर, अन्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों के विरुद्ध किस प्रकार तुलना करता है। जितनी लंबी लाइनें होंगी, केंद्र शासित प्रदेश उतना ही बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। 'सबसे खराब मान' और 'सर्वोत्तम मान' उस सूचक के उच्चतम एवं निम्नतम परिणामों को इंगित करते हैं।

बजट

	राज्य का मान	राज्य के अंक (10 में से)	सबसे खराब मान	सबसे अच्छा मान	राज्य रैंक
उपयोग किया गया मॉडर्नाइजेशन फंड (% , 2016-17)	NA		NA	80	
प्रति व्यक्ति पुलिस पर व्यय (रुपये, 2015-16)	3,283		166	3,283	

कांस्टेबलों की संख्या स्वीकृत पदों से अधिक है, जबकि अधिकारियों के रिक्त पद 10% से कम पर रुके हुए हैं।

मानव संसाधन

कांस्टेबलों, रिक्ति (% , जनवरी 2017)	-1.9		23.3	-6.3
अधिकारी, रिक्ति (% , जनवरी 2017)	8.6		65.6	8.6
सिविल पुलिस में अधिकारी (% , जनवरी 2017)	17.8		6.5	17.8

विविधता

पुलिस में महिलाओं का हिस्सेदारी (% , जनवरी 2017)	8.6		7.2	18.0
अधिकारियों में महिलाओं का हिस्सेदारी (% , जनवरी 2017)	9.8		3.1	22.7
अनु. जाति अधिकारी, आरक्षित अनुपात में वास्तविक (% , जनवरी 2017)	92		22	588
अनु. जनजाति अधिकारी, आरक्षित अनुपात में वास्तविक (% , जनवरी 2017)	98		26	222
अ.पि.व. अधिकारी, आरक्षित अनुपात में वास्तविक (% , जनवरी 2017)	16		0	91

पुलिस में 10% से कम महिलाएं हैं। जहां अनु. जाति और अनु. जनजाति कोटे में आंशिक कमी हुई, वहीं अ.पि.व. आरक्षण को पूरा करने में समर्थ नहीं थे।

अवसंरचना

जनसंख्या प्रति पुलिस स्टेशन (ग्रामीण) (जनवरी 2017)	NA		183,114	884
जनसंख्या प्रति पुलिस स्टेशन (शहरी) (जनवरी 2017)	95,725		160,595	25,841
क्षेत्र प्रति पुलिस स्टेशन क्षेत्र (ग्रामीण) (वर्ग कि.मी., जनवरी 2017)	NA		445	1
क्षेत्र प्रति पुलिस स्टेशन (शहरी) (वर्ग कि.मी., जनवरी 2017)	7		46	5

कार्यभार

जनसंख्या प्रति नागरिक पुलिस (व्यक्ति, जनवरी 2017)	223		1,017	106
---	-----	--	-------	-----

इस केंद्र शासित प्रदेश में शहरी पुलिस स्टेशनों का तीसरी सबसे अच्छी क्षेत्र व्याप्ति है।

रुझान

कुल पुलिस में महिलाएं (प्रतिशत अंक, कैलेंडर वर्ष '12-'16)	0.30		0.16	1.62
कुल अधिकारियों में महिला अधिकारी (प्रतिशत अंक, कैलेंडर वर्ष '12-'16)	0.46		-0.38	2.91
कांस्टेबल रिक्ति (प्रतिशत अंक, कैलेंडर वर्ष '12-'16)	-1.24		2.91	-4.51
अधिकारी रिक्ति (प्रतिशत अंक, कैलेंडर वर्ष '12-'16)	0.75		6.18	-3.38
व्यय में अंतर: पुलिस बनाम राज्य (प्रतिशत अंक, वित्तीय वर्ष '12-'16)	-3.63		-3.63	11.92

डेटा स्रोत : विभिन्न पुलिस संगठन, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी.पी.आर. एंड डी.), भारत में संघ और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त एवं राजस्व लेखे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, प्राथमिक जनगणना सार, जनगणना 2011; ओपन बजट्स इंडिया।

टिप्पणियां : 1. 'जनवरी 2017' हेतु डेटा, दिनांक 1 जनवरी, 2017 तक के अनुसार है। 2. एस.सी.: अनु. जाति; एस.टी.: अनु. जनजाति; ओ.बी.सी.: अन्य पिछड़ा वर्ग। 3. पी.पी.: प्रतिशत अंक। 4. एन.ए.: उपलब्ध नहीं।

5. सी.वाई.: कैलेंडर वर्ष; एफ.वाई.: वित्तीय वर्ष। 6. सिविल पुलिस में जिला सशस्त्र रिजर्व पुलिस भी सम्मिलित है। 7. उपयोग किया गया मॉडर्नाइजेशन फंड: इस पर न तो कोई योगदान और न ही उपयोग डेटा उपलब्ध था।

8. जनसंख्या/क्षेत्र प्रति पुलिस स्टेशन (ग्रामीण) : पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो 0 (शून्य) ग्रामीण पुलिस स्टेशन दर्शाता है। 9. मॉडर्नाइजेशन ग्रांट केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश (पुदुचेरी) के लिए उपलब्ध है। उपलब्ध मूल्य को 'सर्वश्रेष्ठ मूल्य' के रूप में लिया जाता है और संकेतक के लिए 'अत्यंत खराब मूल्य' या अंक नहीं दिया गया है।



जेलें

डेटा को कैसे पढ़ें : चूंकि प्रत्येक संकेतक की एक अलग इकाई होती है, इसलिए तुलना करने के लिए, हमने 1 से 10 के बैंग में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन की गणना करने हेतु मूल्यों के लिए एक नया आधार स्तर तैयार किया है। लाइन ग्राफ यह दर्शाता है कि केंद्र शासित प्रदेश, प्रत्येक संकेतक पर, अन्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों के विरुद्ध किस प्रकार तुलना करता है। जितनी लंबी लाइन होगी, केंद्र शासित प्रदेश उतना ही बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। 'सबसे खराब मान' और 'सर्वोत्तम मान' उस सूचक के उच्चतम एवं निम्नतम परिणामों को इंगित करते हैं।

बजट

	राज्य का मान	राज्य के अंक (10 में से)	सबसे खराब मान	सबसे अच्छा मान
प्रति कैदी व्यय (रु., 2016-17)	52,141		0	67,797
उपयोग किया गया जेल बजट (% , 2016-17)	96		0	100

पूरे केंद्र शासित प्रदेश में जेल स्टाफ की बहुत अधिक रिक्तियां हैं। पांच वर्षों में, अधिकारी और कैडर स्टाफ के कर्मचारियों की रिक्तियों में वृद्धि हुई।

मानव संसाधन

अधिकारी, रिक्ति (% , दिसंबर 2016)	55.5		55.5	0.0
कैडर स्टाफ रिक्ति (% , दिसंबर 2016)	48.2		48.2	0.0
करेक्शनल स्टाफ रिक्ति (% , दिसंबर 2016)	75.9		NA	75.9
चिकित्सा कर्मचारी, रिक्ति (% , दिसंबर 2016)	39.2		39.2	0.0
चिकित्सा अधिकारी, रिक्ति (% , दिसंबर 2016)	51.5		51.5	0.0

विविधता

जेल स्टाफ में महिलाएं (% , दिसंबर 2016)	15.2		5.7	15.2
---	------	--	-----	------

6,000 से अधिक कैदियों पर 12 जेलों ने क्षमता से परे काम किया। पांच वर्षों में, विचाराधीन कैदियों की आबादी बढ़ी।

अवसंरचना

जेल अध्यावास (% , दिसंबर 2016)	180		200	11
--------------------------------	-----	--	-----	----

कार्यभार

कैदी प्रति अधिकारी (व्यक्ति, दिसंबर 2016) कैदी	78		192	30
कैदी प्रति कैडर स्टाफ (व्यक्ति, दिसंबर 2016)	13		13	2
कैदी प्रति करेक्शनल स्टाफ (व्यक्ति, दिसंबर 2016)	2,008		NA	2,008

29 में से केवल 7 ही करेक्शनल स्टाफ उपलब्ध हैं। इसका अर्थ है कि 1 करेक्शनल अधिकारी 2000 से अधिक कैदियों की देखभाल करता है।

रुझान

अधिकारी रिक्ति (प्रतिशत अंक, कैलेंडर वर्ष '12-'16)	7.54		7.54	-5.51
कैडर स्टाफ रिक्ति (प्रतिशत अंक, कैलेंडर वर्ष '12-'16)	4.50		4.50	-3.08
जेल स्टाफ में महिलाओं का हिस्सेदारी (प्रतिशत अंक, कैलेंडर वर्ष '12-'16)	0.30		-0.17	0.65
कैदी प्रति जेल अधिकारी (% , कैलेंडर वर्ष '12-'16)	1.7		27.6	-25.8
कैदी प्रति कैडर स्टाफ (% , कैलेंडर वर्ष '12-'16)	-0.6		19.4	-25.4
विचाराधीन बंदियों की हिस्सेदारी (प्रतिशत अंक, कैलेंडर वर्ष '12-'16)	0.87		5.29	-4.17
प्रति कैदी व्यय (% , वित्तीय वर्ष '13-'17)	-2.0		-86.1	30.4
उपयोग किया गया जेल बजट (प्रतिशत अंक, वित्तीय वर्ष '13-'17)	-0.80		-7.80	0.37
व्यय में अंतर : जेल बनाम राज्य (प्रतिशत अंक, वित्तीय वर्ष '12-'16)	-7.1		-7.1	35.8

डेटा स्रोत : जेल सांख्यिकी भारत (पी.एस.आई), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.); भारत में संघ और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त एवं राजस्व खाते; भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक; प्राथमिक जनगणना सार, जनगणना 2011; ओपन बजट्स इंडिया।

टिप्पणियां : 1.'दिसंबर 2016' हेतु डेटा, दिनांक 31 दिसंबर, 2016 तक के अनुसार है। 2. पी.पी.: प्रतिशत अंक। 3. एन.ए.: उपलब्ध नहीं। 4. सी.वाई.: कैलेंडर वर्ष; एफ.वाई.: वित्तीय वर्ष। 5. सुधारक कर्मचारी डेटा केवल एक केंद्र शासित प्रदेश (दिल्ली) के लिए उपलब्ध है। उस उपलब्ध मूल्य को 'सर्वोत्तम मूल्य' के रूप में लिया जाता है और कोई 'सबसे खराब मूल्य' या स्कोर दो संकेतकों के लिए निर्दिष्ट नहीं किया गया है: सुधारक कर्मचारी, वैकेंसी; सुधारक कर्मचारी प्रति कैदी।



न्यायपालिका

डेटा को कैसे पढ़ें : चूंकि प्रत्येक संकेतक की एक अलग इकाई होती है, इसलिए तुलना करने के लिए, हमने 1 से 10 के बैंग में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन की गणना करने हेतु मूल्यों के लिए एक नया आधार स्तर तैयार किया है। लाइन ग्राफ यह दर्शाता है कि केंद्र शासित प्रदेश, प्रत्येक संकेतक पर, अन्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों के विरुद्ध किस प्रकार तुलना करता है। जितनी लंबी लाइन होगी, केंद्र शासित प्रदेश उतना ही बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। 'सबसे खराब मान' और 'सर्वोत्तम मान' उस सूचक के उच्चतम एवं निम्नतम परिणामों को इंगित करते हैं।

बजट

	राज्य का मान	राज्य के अंक (10 में से)	सबसे खराब मान	सबसे अच्छा मान
न्यायपालिका पर प्रति व्यक्ति व्यय (₹., 2015-16)	453		125	453

मानव संसाधन

जनसंख्या प्रति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (2016-17)	472,900		2,380,693	472,900
जनसंख्या प्रति अधीनस्थ न्यायालय न्यायाधीश (2016-17)	34,366		106,719	23,445
उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश रक्ति (% , 2016-17)	40.8		46.5	26.1
अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीश रक्ति (% , 2016-17)	38.2		49.0	0.0
उच्च न्यायालयों में कर्मचारी रक्ति (% , 2016-17)	29.7		31.1	5.5

दोनों न्यायालयों में बहुत अधिक रक्तियां हैं।

विविधता

महिला न्यायाधीश (उच्च न्यायालय) (% , जून 2018)	20.5		12.2	20.5
महिला न्यायाधीश (अधीनस्थ न्यायालय) (% , जुलाई 2017)	33.8		0.0	41.7

केंद्र शासित प्रदेशों में महिला उच्च न्यायालय न्यायाधीशों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व है। अधीनस्थ न्यायालयों में, 3 में से 1 न्यायाधीश महिलाएं हैं।

अवसरचना

न्यायालय कक्षों की कमी (% , 2016-17, मार्च 2018)	39.0		39.0	0.0
--	------	--	------	-----

कार्यभार

लंबित प्रकरण (5-10 वर्ष) (अधीनस्थ न्यायालय) (% , अगस्त 2018)	6.24		19.10	1.80
लंबित प्रकरण (10+ वर्ष) (अधीनस्थ न्यायालय) (% , अगस्त 2018)	0.79		8.18	0.15
उच्च न्यायालयों में लंबित प्रकरण (वर्ष, सितंबर 2017)	3.4		3.7	2.5
अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित प्रकरण (वर्ष, अगस्त 2017)	3.9		8.4	3.9
प्रकरण निपटान दर (उच्च न्यायालय) (% , 2016-17)	91		81	101
प्रकरण निपटान दर (अधीनस्थ न्यायालय) (% , 2016-17)	87		87	110

अधीनस्थ न्यायालयों में सबसे कम मामलों की निकासी दर के बावजूद, लगभग 4 वर्षों तक लंबित रहे मामले, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम थे।

रुझान

लंबित प्रकरण (प्रति उच्च न्यायालय न्यायाधीश) (% , FY '13-'17)	2.4		4.3	-6.8
लंबित प्रकरण (प्रति उप-न्यायालय न्यायाधीश) (% , वित्तीय वर्ष '13-'17)	-3.8		25.0	-14.1
कुल लंबित प्रकरण (उच्च न्यायालय) (% , वित्तीय वर्ष '13-'17)	1.4		5.5	-8.4
कुल लंबित प्रकरण (अधीनस्थ न्यायालय) (% , वित्तीय वर्ष '13-'17)	-2.9		12.3	-8.0
न्यायाधीश रक्ति (उच्च न्यायालय) (प्रतिशत अंक, वित्तीय वर्ष '13-'17)	3.48		3.53	1.00
न्यायाधीश रक्ति (अधीनस्थ न्यायालय) (प्रतिशत अंक, वित्तीय वर्ष '13-'17)	2.64		2.81	-5.00
प्रकरण निपटान दर (उच्च न्यायालय) (प्रतिशत अंक, वित्त वर्ष '13-'17)	-3.53		-3.53	3.50
प्रकरण निपटान दर (अधीनस्थ न्यायालय) (प्रतिशत अंक, वित्त वर्ष '13-'17)	-7.35		-7.35	7.81
व्यय में अंतर : न्यायपालिका बनाम राज्य (प्रतिशत अंक, वित्तीय वर्ष '12-'16)	-0.02		-0.02	3.10

आंकड़ों के स्रोत : कोर्ट न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया; नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड; ई-कोर्ट सेवाएँ; उच्च न्यायालयों की वेबसाइटें; एप्रोच टू जस्टिस इन इंडिया; दक्ष (DAKSH) द्वारा एक रिपोर्ट; भारत में संघ और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व लेखे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक; प्राथमिक जनगणना सार, जनगणना 2011; सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा दायर आवेदन; ओपन बजट्स इंडिया; न्याय विभाग।
टिप्पणियाँ : 1. आंकड़े 'अगस्त 2018' हेतु 23 अगस्त 2018 पर; 'सितंबर 2017' हेतु 19 सितंबर, 2017 पर; तथा 'अगस्त 2017' हेतु 29 अगस्त, 2017 पर आधारित हैं।
2. अथी. अदालत : अधीनस्थ अदालत 3. पीपी: प्रतिशत अंक 4. एनए: उपलब्ध नहीं 5. सीवाई: कैलेंडर वर्ष; एफवाई: वित्तीय वर्ष



विधिक सहायता

डेटा को कैसे पढ़ें : चूंकि प्रत्येक संकेतक की एक अलग इकाई होती है, इसलिए तुलना करने के लिए, हमने 1 से 10 के बैज में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन की गणना करने हेतु मूल्यों के लिए एक नया आधार स्तर तैयार किया है। लाइन ग्राफ यह दर्शाता है कि केंद्र शासित प्रदेश, प्रत्येक संकेतक पर, अन्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों के विरुद्ध किस प्रकार तुलना करता है। जितनी लंबी लाइन होगी, केंद्र शासित प्रदेश उतना ही बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। 'सबसे खराब मान' और 'सर्वोत्तम मान' उस सूचक के उच्चतम एवं निम्नतम परिणामों को इंगित करते हैं।

बजट

	राज्य का मान	राज्य के अंक (10 में से)	सबसे खराब मान	सबसे अच्छा मान
उपयोग की गई रा.वि.से.प्रा. निधि (% , 2017-18)	68		4	68
विधिक सहायता व्यय में राज्य की हिस्सेदारी (% , 2017-18)	49		0	49

मानव संसाधन

जि.वि.से.प्रा. में सचिव रिक्ति (% , 2019)	0.0		100.0	0.0
पैरा लीगल वॉलंटियर प्रति लाख जनसंख्या (संख्या, जनवरी 2019)	7.6		0.9	69.8
जि.वि.से.प्रा. के स्वीकृत सचिव (% , 2019)	100		0	100

अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के बीच, विधिक सहायता हेतु सबसे बड़ा राज्य योगदान रहा।

विविधता

महिला पैनल अधिवक्ता (% , जनवरी 2019)	27.3		24.1	50.0
महिला पैरा लीगल वॉलंटियर (% , जनवरी 2019)	47.3		41.4	67.8

अवसंरचना

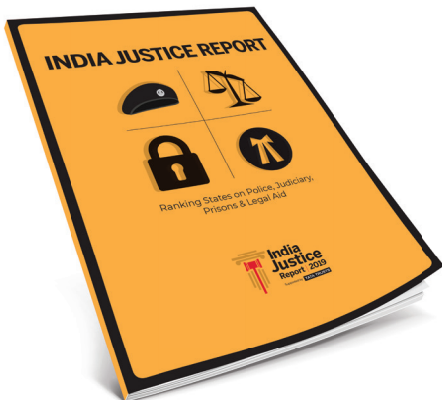
राज्य न्यायिक जिलों के % के रूप में जि.वि.से.प्रा. (% , 2019)	100		0	100
ग्राम प्रति विधिक सेवाएं क्लिनिक (संख्या, 2017-18)	0.0		5.4	0.0
विधिक सेवाएं क्लिनिक प्रति जेल (संख्या, 2017-18)	1.42		0.00	1.42

दिल्ली की प्रत्येक जेल में औसतन एक कार्यशील विधिक सेवा क्लिनिक था।

कार्यभार

स्थायी लोक अदालत प्रकरण : प्राप्त प्रकरणों के % के रूप में निराकृत (% , 2017-18)	94		0	121
कुल लोक अदालतें : मुकदमा-पूर्व प्रकरणों का निपटारा (% , 2017-18) *	31.0		3.4	100.0
रा.वि.से.प्रा. लोक अदालतें : लिए गए प्रकरणों में प्री-लिटिगेशन (% , 2017-18) **	86.5		0.0	86.5

आंकड़ों के स्रोत : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा); प्राथमिक जनगणना सार, जनगणना 2011; मिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया (पीएसआई), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), टिप्पणियां : 1. डीएलएसए : जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण; एलए : लोक अदालत; पीएलए : स्थायी लोक अदालत; पीएलवी : पैरा-लीगल वॉलंटियर; एसएलएसए : राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण।
2. गांव प्रति विधिक सेवाएं क्लिनिक : कोई विधिक सेवा क्लिनिक नहीं है।
पूर्ण संकेतक : *एलएलए + एसएसएसए एलए : विचारार्थी मामलों (% , 2017-18) में पूर्व-मुकदमेबाजी मामलों की हिस्सेदारी; ** एसएसएसए एलए : कुल लिए गए मामलों (% , 2017-18) के % के रूप में लिए गए पूर्व-मुकदमेबाजी के मामले;



इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बारे में :

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 प्रथम व्यापक मात्रात्मक सूचकांक प्रदान करती है जो विभिन्न राज्यों में औपचारिक न्याय प्रणाली की क्षमता को पुलिस, जेलों, न्यायपालिका एवं विधिक सहायता पर संचालित औपचारिक न्याय प्रणाली की क्षमता को रैंक प्रदान करता है। इस रैंकिंग को टाटा ट्रस्ट द्वारा दक्ष, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और टी.आई.एस.एस.-प्रयास की साझेदारी में समर्थित किया गया था एवं सुसाध्य बनाया गया था।

मुख्य रिपोर्ट, रैंकिंग और कार्यपद्धति, डेटा वि.जुअलाइजेशन, संबंधित अनुसंधान एवं और अधिक जानकारी हेतु www.tatatrusts.org पर जाएं।

डेटा एवं डिज़ाइन : हाउ इंडिया लिक्स